लंबित मामलों को शीघ्र निपटाएं

सुप्रीम कोर्ट सख्त, देरी पर हाईकोर्टों को निर्देश

नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने देशभर के हाईकोर्ट में लंबित मामलों और फैसलों में हो रही देरी पर गंभीर चिंता जताई है. कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि किसी भी मामले में फैसला सुरक्षित (रिजर्व) रखने के बाद उसे अधिकतम 3 महीने के भीतर अनिवार्य रूप से सुनाया जाना चाहिए.

यदि ऐसा नहीं होता है, तो संबंधित हाईकोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को मामला चीफ जस्टिस के संज्ञान में लाना होगा. सीजेआई सूर्यकांत की अगुआई वाली बेंच ने यह भी निर्देश दिया कि जमानत

याचिकाओं पर निर्णय उसी दिन सुनाया जाए और यदि आदेश सुरक्षित रखा गया है तो उसे अगले दिन जारी कर वेबसाइट पर अपलोड किया जाए.

यह निर्देश झारखंड हाईकोर्ट में 2022 से लंबित एक आपराधिक अपील के मामले की सुनवाई के दौरान दिए गए, जिसमें देरी को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार का उल्लंघन बताया गया. सुप्रीम कोर्ट ने कुल 12 निर्देश जारी किए हैं, जिनमें जमानत मामलों की त्वरित सुनवाई, जेल प्रशासन को तुरंत सूचना भेजना, और फैसलों की समयबद्ध अपलोडिंग शामिल है. कोर्ट ने कहा कि यदि 3 महीने से अधिक देरी होती है तो पक्षकार 2 दिन के भीतर सुनवाई की मांग कर सकते हैं, और 4 महीने बाद मामला दूसरी बेंच को स्थानांतरित करने की अपील भी की जा सकती है. सीजेआई ने कहा कि न्याय में देरी स्वीकार नहीं की जा सकती.

पूर्व सीजेआई बीआर गवई बोले, विवाद बढ़ा-चढ़ाकर पेश

नई दिल्ली, 29 मई. पूर्व मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई ने सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान उपयोग किए गए कुछ शब्दों को लेकर उठे विवाद पर प्रतिक्रिया दी है. इस दौरान उनसे पूछा गया कि सुप्रीम कोर्ट में बेरोजगारों को 'कॉकरोच' और 'पैरासाइट' जैसे शब्द कहे गए, आप इसे कैसे देखते हैं? उन्होंने कहा कि इस मुद्दे को बेवजह बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया जा रहा है और जज भी इंसान होते हैं, इसलिए सुनवाई के दौरान अनजाने में कोई शब्द निकल सकता है, जिसका गलत अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिए. मीडिया को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के कारण संदर्भ से हटकर बातों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया जाता है.

तेलंगाना सरकार ने जारी किये 2,000 करोड़

हैदराबाद. तेलंगाना सरकार ने शुक्रवार को पहले चरण के तहत कर्मचारियों के लंबे समय से लंबित बकाये भुगतान के लिए 2,000 करोड़ जारी कर दिये हैं. इसके साथ ही सरकार ने मुख्यमंत्री ए रेवंत रेड्डी और उपमुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्क ने कर्मचारी यूनियनों को दिये एक प्रमुख आश्वासन को पूरा कर दिया है. सरकार ने इससे पहले कर्मचारी संयुक्त कार्रवाई समिति के नेताओं से वादा किया था कि 6,000 करोड़ का लंबित बकाया 100 दिनों के भीतर चुका दिया जायेगा. वित्त मंत्री भट्टी विक्रमार्क के निर्देशों पर कार्रवाई करते हुए वित्त विभाग के विशेष मुख्य सचिव संदीप कुमार सुल्तानिया ने शुक्रवार को 2,000 करोड़ जारी करने के आदेश जारी किये.

निर्माणाधीन पुल का स्लैब गिरने से 6 की मौत

सहायक अभियंता गजेंद्र कुमार चौधरी को निलंबित कर दिया

लखनऊ, 29 मई . उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में बेतवा नदी पर बन रहे निर्माणाधीन पुल का स्लैब शुक्रवार देर रात करीब 2 बजे गिर गया. इस दर्दनाक हादसे में 6 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि एसडीआरएफ की टीम ने मलबे में फंसे 3 मजदूरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया. करीब साढ़े 7 घंटे तक रेस्क्यू ऑपरेशन चला.

उत्तर प्रदेश ब्रिज कॉरपोरेशन के अनुसार, हादसा तेज आंधी और बारिश के कारण हुआ, जब 70-80 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल रही थीं. घटना के बाद सहायक अभियंता गजेंद्र

कुमार चौधरी को निलंबित कर दिया गया है, जबकि डीपीएम दिलीप कुमार के खिलाफ विभागीय कार्रवाई शुरू कर दी गई है. हादसा हमीरपुर से लगभग 25 किलोमीटर दूर ललपुरा क्षेत्र में हुआ. मृतकों में 4 मजदूर बांदा और 2 हमीरपुर के रहने वाले थे. निर्माणाधीन पुल लगभग 700 मीटर लंबा है और इसकी लागत 90 करोड़ रुपये बताई जा रही है. इसका निर्माण मार्च 2024 में शुरू हुआ था और इसे दिसंबर 2026 तक पूरा किया जाना है. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, आंधी के दौरान मजदूर पुल के नीचे और ऊपर दोनों जगह मौजूद थे. अचानक स्लैब गिरने से कई मजदूर दब गए. जेसीबी और एसडीआरएफ की मदद से राहत एवं बचाव कार्य चलाया गया.

वज्रपात से 7 की मौत

पटना, 29 मई . बिहार में शुक्रवार को वज्रपात (बिजली गिरने) की घटनाओं में 7 लोगों की मौत हो गई. आंधी-बारिश और बिजली गिरने की घटनाएं औरंगाबाद, गया, सारण और खगड़िया जिलों में दर्ज की गई. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने मृतकों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करते हुए प्रत्येक मृतक के आश्रित को 4-4 लाख रुपये अनुग्रह अनुदान देने के निर्देश दिए हैं.

आर्ट ऑफ लिविंग समारोह में उपराष्ट्रपति ने जारी किया स्मारक डाक टिकट

बेंगलुरु, 29 मई .भारत के उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन ने शुक्रवार वर्ष पूरे होने के अवसर पर आयोजित भव्य समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन ने स्मारक डाक टिकट जारी किया और पांच राष्ट्रीय पहलों की शुरुआत की. इस दौरान उन्होंने संस्था के सामाजिक, मानवीय और वैश्विक शांति में योगदान की सराहना की.

कार्यक्रम आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल सेंटर में आयोजित हुआ, जिसमें 678 से अधिक विशिष्ट अतिथि शामिल हुए. उपराष्ट्रपति ने कहा कि आंतरिक शांति ही बाहरी सद्भाव की नींव है और वर्तमान समय में ध्यान, योग और आध्यात्मिक मूल्यों का

महत्व और बढ़ गया है.पांच पहलों में यूथ करियर एक्सीलेंस प्रोग्राम, ईस्टर्न नॉलेज सिस्टम्स, इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप इनक्यूबेशन, कॉन्शियसनेस स्टडीज सेंटर और 'इको शांति' पहल शामिल हैं. इनका उद्देश्य शिक्षा, स्टार्टअप, शोध, पर्यावरण संरक्षण और मानव विकास को बढ़ावा देना है.

'इको शांति' पहल के तहत 2030 तक हर साल 1 लाख टन प्लास्टिक उपयोग कम करने का लक्ष्य रखा गया है.

आज का इतिहास

1381 – इंग्लैंड के एसेक्स में किसानों का विद्रोह शुरु।
1539 – स्पेन के हर्नान्डो डी सोटो ने फ्लोरिडा की खोज की।
1606 – सिखों के पांचवें गुरु अर्जुन देव का निधन।
1646 – स्पेन और नीदरलैंड ने युद्धविराम समझौते पर हस्ताक्षर किये।
1778 – महान फ्रांसीसी दार्शनिक और लेखक वॉल्तेयर का निधन।
1966 – अमेरिकी विमानों ने उत्तरी वियतनाम पर बमबारी की।
1987 – गोवा देश का 25वां पूर्ण राज्य बना।
2012 – ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन ने पांचवीं विश्व शतरंज चैम्पियनशिप जीती।

'ऑपरेशन सिंदूर' पर पुस्तक का हुआ विमोचन

पुस्तक पारंपरिक सैन्य इतिहास से अलग : राजनाथ

नई दिल्ली, 29 मई . रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने 'ऑपरेशन सिंदूर' को अंजाम देने वाले बहादुर सैनिकों, नौसैनिकों और वायु सैनिकों के अनुभवों पर आधारित स्मारक पुस्तक का विमोचन किया. इस अवसर पर उन्होंने इसे सैनिकों के साहस, समर्पण और राष्ट्रसेवा का प्रतीक बताया.

इस पुस्तक में ऑपरेशन में शामिल करीब 100 सैन्य कर्मियों के व्यक्तिगत अनुभवों को संकलित किया गया है, जिसमें युद्ध के दौरान जमीनी हालात, हवाई कार्रवाई, नौसैनिक रणनीति और विशेष बलों की भूमिका का

विस्तृत वर्णन किया गया है. राजनाथ सिंह ने कहा कि यह पुस्तक पारंपरिक सैन्य इतिहास से अलग है, क्योंकि इसमें ऑपरेशन के वास्तविक अनुभवों को सीधे सैनिकों की नजर से प्रस्तुत किया गया है. उन्होंने इसे आधुनिक युद्ध में नेतृत्व, निर्णय क्षमता और साहस का जीवंत दस्तावेज बताया.

उन्होंने यह भी कहा कि भारत ने इस ऑपरेशन के दौरान चार दिनों में ही पाकिस्तान को युद्धविराम के लिए मजबूर किया, जो भारतीय सेनाओं की ताकत और रणनीतिक दक्षता को दर्शाता है. इस मौके पर प्रमुख रक्षा अध्यक्ष जनरल अनिल चौहान, तीनों सेनाओं के प्रमुख और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे.

सहारनपुर पुलिस मुठभेड़ में 1 लाख का इनामी बदमाश ढेर

लखनऊ, 29 मई . उत्तर प्रदेश के सहारनपुर जिले के थाना चिलकाना क्षेत्र में शुक्रवार को पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई. इस दौरान एक लाख रुपये का इनामी बदमाश एहसान मारा गया, जबकि उसका एक साथी जंगल के रास्ते फरार हो गया.

पुलिस के अनुसार, टीम संदिग्ध बदमाशों की तलाश में इलाके में दबिश दे रही थी, तभी दो संदिग्धों ने अचानक फायरिंग शुरू कर दी. जवाबी कार्रवाई में दोनों ओर से काफी देर तक गोलीबारी हुई, जिसमें बदमाश एहसान को सीने और पैर में गोली लगी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई. इस मुठभेड़ में थाना सरसावा प्रभारी इंस्पेक्टर प्रवेश शर्मा और हेड कांस्टेबल सोनू भी घायल हो गए. इंस्पेक्टर की बुलेटप्रूफ जैकेट में गोलियां लगने से उनकी जान बच गई. दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है. पुलिस ने मौके से हथियार और कारतूस बरामद किए हैं. मारे गए बदमाश एहसान पर लूट समेत कई गंभीर मामलों में 13 से अधिक मुकदमे दर्ज थे और वह थाना बेहट क्षेत्र की एक बड़ी लूट में वांछित था. घटना के बाद पूरे इलाके में पुलिस बल तैनात कर दिया गया है और फरार बदमाश की तलाश के लिए जंगलों में ड्रोन और सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है.

एक नजर में

भेड़ चराने को तैयार यूनिवर्सिटी टॉपर

बीजिंग, 29 मई . चीन में बढ़ते रोजगार संकट और खराब वर्किंग कल्चर का असर अब इस हद तक दिखने लगा है कि कई लोग महानगरों की अच्छी नौकरियां छोड़कर

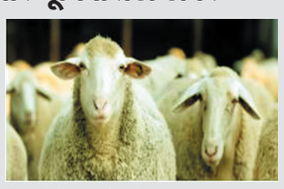

गांवों में चरवाहे की नौकरी करने को तैयार हैं. सोशल मीडिया पर वायरल एक नौकरी विज्ञापन ने देश के लेबर मार्केट की सच्चाई उजागर कर दी है. मंगोलिया के दक्षिणी घास के मैदानों में चरवाहों की भर्ती के लिए जारी इस विज्ञापन को चीनी प्लेटफॉर्म 'वीबो' पर 5.9 करोड़ से अधिक बार देखा गया. केवल दो पदों के लिए 700 से ज्यादा लोगों ने आवेदन किया, जिनमें शंघाई और चोंगकिंग जैसे बड़े शहरों के व्हाइट-कॉलर कर्मचारी, फैक्ट्री वर्कर और हाल ही में स्नातक हुए युवा शामिल हैं. इस नौकरी के लिए लगभग 8,000 युआन (करीब 1.1 लाख रुपये) मासिक वेतन के साथ रहने और खाने की सुविधा भी दी जा रही है, जो चीन के औसत शहरी वेतन से अधिक है. यही कारण है कि युवा भारी कर्ज, ऑफिस प्रेशर और फैक्ट्री की कठिन परिस्थितियों से परेशान होकर इस तरह के काम की ओर आकर्षित हो रहे हैं.

रूस में लैंड करते ही पुतिन-तालिबान में हुई डील

नई दिल्ली, 29 मई. रूस में आयोजित इंटरनेशनल सिक्योरिटी फोरम के दौरान भारत, रूस और अफगानिस्तान के बीच बदलते भू-राजनीतिक समीकरण सामने आए. भारत के

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने आतंकवाद पर सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि इसके खिलाफ लड़ाई में किसी भी तरह का 'दोहरा मापदंड' स्वीकार नहीं किया जाएगा. उन्होंने बिना किसी देश का नाम लिए वैश्विक समुदाय को आतंकवाद के प्रायोजकों के खिलाफ एकजुट कार्रवाई का संदेश दिया. इसी मंच के इतर रूस और तालिबान के बीच सैन्य सहयोग समझौते की चर्चा ने क्षेत्रीय तनाव को और बढ़ा दिया है. रिपोर्ट्स के अनुसार, अफगानिस्तान ने एयर डिफेंस सिस्टम की मांग की है, जिससे भविष्य में उसकी सैन्य क्षमता मजबूत हो सकती है. विशेषज्ञों का मानना है कि यदि रूस अफगानिस्तान को रक्षा उपकरण या प्रशिक्षण सहायता देता है, तो पाकिस्तान की सुरक्षा रणनीति पर असर पड़ सकता है, क्योंकि अभी तक उसके पास तकनीकी बढ़त मानी जाती थी. दूसरी ओर, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने तालिबान और भारत पर आरोप लगाते हुए बयान दिया, जिससे क्षेत्रीय तनाव और बढ़ गया है. वहीं तालिबान ने हिंदू और सिख समुदायों को अफगानिस्तान लौटने का निमंत्रण देकर खुद को एक 'व्यवस्थित शासन' के रूप में प्रस्तुत करने की कोशिश की है.

खतरे के बीच होर्मुज पार कर रहे भारतीय जहाज, सरकार सतर्क

तेल सप्लाई बचाने को सरकार का गुप्त समन्वय

नई दिल्ली, 29 मई. ईरान-अमेरिका तनाव के बीच दुनिया के सबसे संवेदनशील समुद्री मार्ग स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर वैश्विक चिंता बढ़ गई है। यह वही समुद्री रास्ता है, जहां से दुनिया के करीब 20 प्रतिशत तेल और ऊर्जा आपूर्ति गुजरती है।

हालात इतने तनावपूर्ण हैं कि कई देशों ने जहाजों की आवाजाही सीमित कर दी है, लेकिन भारत ने रणनीतिक समन्वय और कूटनीतिक प्रयासों के जरिए अपने जहाजों को सुरक्षित निकालने में सफलता हासिल की है. शिपिंग मंत्रालय के डायरेक्टर ओपेश कुमार शर्मा ने बताया कि मार्शल आइलैंड्स के झंडे वाला क्रूड ऑयल टैंकर 'निसोस केरोस' 25-26 मई की रात सुरक्षित रूप से स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पार कर चुका है। यह जहाज लगभग 2.7 लाख मीट्रिक टन कच्चा तेल लेकर भारत आ रहा है और इसके 3 जून तक विशाखापत्तनम पहुंचने की संभावना है। सुरक्षा कारणों से जहाजों की आवाजाही और ईरान के साथ समन्वय की पूरी जानकारी साझा नहीं की जा सकती. विदेश मंत्रालय, पेट्रोलियम मंत्रालय और उर्वरक मंत्रालय मिलकर तय करते हैं कि किस जहाज को पहले सुरक्षित निकाला जाएगा.

1 से 30 जून तक 'खेत बचाओ अभियान' चलेगा : शिवराज

9.76 करोड़ फार्मर आईडी बनकर तैयार

योजनाओं का लाभ अब होगा और आसान

नई दिल्ली, 29 मई . केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिल्ली में आयोजित राष्ट्रीय खरीफ कृषि सम्मेलन में खरीफ 2026 की तैयारियों को लेकर व्यापक जानकारी दी.

उन्होंने कहा कि देश पूरी तरह तैयार है और इस बार कृषि व्यवस्था को पहले से अधिक वैज्ञानिक, पारदर्शी और किसान-केंद्रित बनाया गया है. उन्होंने बताया कि खरीफ 2026 के लिए

देश में लगभग 173 लाख क्विंटल बीज की आवश्यकता है, जबकि 192 लाख क्विंटल बीज उपलब्ध है, यानी जरूरत से करीब 11 प्रतिशत अधिक गुणवत्तायुक्त बीज उपलब्ध कराया गया है. मौसम की अनिश्चितताओं को देखते हुए 1.74 लाख क्विंटल का राष्ट्रीय बीज भंडार भी तैयार किया गया है, ताकि किसी भी आपात स्थिति में किसानों को समय पर सहायता मिल सके.

किसानों को योजनाओं का लाभ आसानी से देने के लिए अब तक 9.76 करोड़ फार्मर आईडी तैयार की जा चुकी हैं, जिससे खाद, सहायता और अन्य योजनाओं का वितरण अधिक पारदर्शी होगा. केंद्रीय मंत्री ने बताया कि कृषि ऋण, फसल बीमा और नकली कीटनाशकों पर नियंत्रण को लेकर भी ठोस रूपरेखा बनाई गई है. श्री चौहान ने कहा कि 1 से 30 जून तक 'खेत बचाओ अभियान' चलाया जाएगा, जिसके तहत गांव-गांव जाकर किसानों को संतुलित उर्वरक उपयोग, प्राकृतिक खेती, मशीनीकरण और स्वाइल हेल्थ कार्ड जैसी योजनाओं की जानकारी दी जाएगी. इस दौरान किसान क्रेडिट कार्ड और अन्य सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाएंगी. उन्होंने यह भी बताया कि हर राज्य के लिए अलग कृषि रोडमैप तैयार किया जाएगा.

फसल बीमा योजना में सुधार के लिए क्रॉप कटिंग और रिमोट सेंसिंग आधारित आकलन को मजबूत करने तथा दावों के निपटारे में देरी पर 12% ब्याज लागू करने का निर्णय लिया गया है. साथ ही नकली कृषि आदानों के खिलाफ सख्त अभियान चलाने पर भी सहमति बनी है.

खुली जीप में पिस्टल लहराते हुए हिंदुओं को धमका नहीं सकता

प्रदेश की कई परियोजना को जल्द पूरा करेंगे

मुख्यमंत्री योगी ने मऊ में 392 करोड़ की 114 परियोजनाओं का किया लोकार्पण

मऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को गांधी मैदान में आयोजित कार्यक्रम के दौरान 392 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली 114 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया. इसमें सड़क, पुल, पेयजल, शिक्षा, स्वास्थ्य और पुलिस अवस्थापना से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं. मुख्यमंत्री ने मऊ को 'क्रांतिधरा' बताते हुए यहां के ऐतिहासिक और सामाजिक योगदान को याद किया और पूर्व नेताओं व समाज सुधारकों को श्रद्धांजलि दी.

लखनऊ, 29 मई . मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को मऊ की धरती से माफिया को फिर खुली चुनौती दी. उन्होंने दो टूक कहा कि अब किसी माफिया व गुंडे में दुस्साहस नहीं है कि त्योहारों में उपद्रव कर दे.

यदि किसी ने रामलीला, यज्ञ-कथा, जन्माष्टमी, रामनवमी, शिवरात्रि, रक्षाबंधन आदि धार्मिक आयोजनों में व्यवधान डाला तो उसकी रावण व कंस जैसी दुर्गति तय है. किसी ने बेटी व व्यापारी की सुरक्षा में सेंध लगाई तो उसका इंतजार यमराज ही करेंगे. अब

कोई माफिया खुली जीप में चलकर पिस्टल लहराते हुए किसी हिंदू को धमका नहीं सकता.

उन्होंने कहा कि विकास बिना भेदभाव सभी नागरिकों तक पहुंचना चाहिए और सड़क, पुल, स्वास्थ्य व सुरक्षा जैसी सुविधाएं जाति देखकर नहीं मिलतीं. सीएम योगी ने कहा कि 2017 से पहले यूपी में अराजकता और अपराध का माहौल था, जबकि आज प्रदेश में सुरक्षा और विकास दोनों मजबूत हुए हैं. उन्होंने दावा किया कि आज गरीबों को आवास, शौचालय, मुफ्त राशन और स्वास्थ्य सुविधाएं बड़े पैमाने पर मिल रही हैं. उन्होंने यह भी बताया कि मऊ में 76 परियोजनाओं का शिलान्यास और 38 परियोजनाओं का लोकार्पण किया गया है, जिससे क्षेत्रीय विकास को नई गति मिलेगी. साथ ही उन्होंने घोसी चीनी मिल के विस्तार और मेडिकल कॉलेज परियोजना को जल्द पूरा करने का आश्वासन दिया. सीएम ने डबल इंजन सरकार के विकास मॉडल की सराहना करते हुए कहा कि पूर्वांचल में सड़क, एक्सप्रेसवे और कनेक्टिविटी के कारण अब आवागमन आसान हुआ है.

भ्रष्ट अफसरों पर भजनलाल सख्त

ढाई साल में 103 अधिकारी निलंबित, 6 बर्खास्त

जयपुर, 29 मई .राजस्थान में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने भ्रष्टाचार और लापरवाही के खिलाफ सख्त रुख अपनाते हुए बड़ा प्रशासनिक एक्शन लिया है.

सरकार ने जीरो टॉलरेंस नीति के तहत पिछले ढाई वर्षों में एक आईएएस अधिकारी सहित 103 अधिकारियों को निलंबित किया है, जबकि 6 अधिकारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया.इसके अलावा 11 अधिकारियों की आजीवन पेंशन रोकने और 108 मामलों में अभियोजन स्वीकृति देने जैसी कार्रवाई भी की गई है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि रिश्वत, पद के दुरुपयोग और आय से अधिक संपत्ति के मामलों में दोषी पाए जाने वाले अधिकारियों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा.न्यायालय में दोष सिद्ध होने

के बाद पीडब्ल्यूडी, चिकित्सा विभाग और वित्त कर विभाग से जुड़े कई अधिकारियों को तत्काल प्रभाव से सेवा से बाहर किया गया। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि जनता को पारदर्शी, संवेदनशील और भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन देना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है.उन्होंने चेतावनी दी कि जो अधिकारी जनता के पैसे का दुरुपयोग करेगा, उसकी नौकरी, पेंशन और कानूनी सुरक्षा तीनों खत्म हो सकती हैं।

लोकार्पण जब जवान नहीं थकते हैं तो दूसरों को भी थकने का बिल्कुल अधिकार नहीं है

अब टेरिटोरियल की सुरक्षा करेगी बीएसएफ : अमित शाह

नए क्षेत्रों को भी बीएसएफ को देने पर विचार कर रहे हैं

जी-7 सीमा चौकी पर जवानों से संवाद किया

नई दिल्ली 29 मई. केन्द्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार सीमा सुरक्षा की अवधारणा को पूरी तरह बदलते हुए आने वाले दिनों में एक चतुष्कोणीय सुरक्षा ग्रिड बनायेगी और सीमा की सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा की नयी अवधारणा की शुरूआत करेगी.

श्री शाह ने शुक्रवार को गुजरात के भुज में भारत-पाकिस्तान सीमा पर स्थित जी-7

सीमा चौकी पर जवानों से संवाद किया और जी-7 एवं जी-13 चौकियों का लोकार्पण किया. इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हम स्मार्ट बॉर्डर सिक्युरिटी प्रोजेक्ट के तहत सीमा पर सुरक्षा ग्रिड को मजबूत बनाने का काम कर रहे हैं. इसमें हजारों करोड़ रुपए का निवेश किया जा रहा है और उन्हें विश्वास है कि ड्रोन, रडार, वॉच टावर, अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी और जवानों की तैनाती से एक मजबूत सुरक्षा ग्रिड खड़ी होगी. इसके बाद कोई हमारी सरहद को भेदने की हिम्मत नहीं कर पाएगा. गृह मंत्री ने कहा कि बीएसएफ के जवान बहुत विषम जलवायु और कठिन भौगोलिक परिस्थितियों में रहते हैं और जब जवान नहीं थकते हैं तो दूसरों को भी थकने का बिल्कुल अधिकार नहीं है. उन्होंने कहा कि बीएसएफ ने स्थापना से लेकर अब तक बीते 60 साल में देश की दो सबसे कठिन सीमाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाई है. अगले दो साल में हमारा यह क्षेत्र दुश्मन की बुरी नजर से हमेशा के लिए सुरक्षित हो जाएगा. केन्द्रीय गृह मंत्री ने कहा कि बीएसएफ के जवान सरक्रीक और भुज में चट्टान की तरह खड़े हैं, जिसके कारण भुज की जनता पूरी तरह सुरक्षित है.

गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेन्द्र पटेल, उप-मुख्यमंत्री हर्ष संघवी, केन्द्रीय गृह सचिव, गुप्तचर ब्यूरो के निदेशक, सीमा प्रबंधन सचिव और सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के महानिदेशक सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।सीमा क्षेत्रों की सुरक्षा की नयी अवधारणा का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि बीएसएफ की स्थापना के 60वें साल में हमने बीएसएफ की सीमा सुरक्षा की अवधारणा को पूरी तरह बदलने का निर्णय किया है. उन्होंने कहा कि हम आने वाले दिनों में एक चतुष्कोणीय सुरक्षा ग्रिड बनाएंगे और बॉर्डर की सुरक्षा की जगह टेरिटोरियल सुरक्षा की नयी अवधारणा की शुरूआत करेंगे.

आतंकी नेटवर्क पर एनआइए का प्रहार

यूपी-बिहार समेत चार राज्यों में 12 ठिकानों पर छापेमारी

ड्रोन से हथियार सप्लाई का किया खुलासा

नई दिल्ली, 29 मई. देश में आतंकी साजिश को लेकर राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने शुक्रवार को बड़ा ऑपरेशन चलाया. एजेंसी ने पाकिस्तान से जुड़े आतंकी नेटवर्क के खिलाफ उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान और बिहार में एक साथ 12 ठिकानों पर छापेमारी की. यह कार्रवाई सीमा पार से संचालित उस नेटवर्क को लेकर की गई, जो भारत में बड़े आतंकी हमलों की योजना बना रहा था.

एनआईए अधिकारियों के अनुसार, जांच में सामने आया है कि इस पूरे मॉड्यूल का संचालन पाकिस्तान में बैठे जसवीर चौधरी नामक हैंडलर द्वारा किया जा रहा था. आरोप है कि उसने भारत में मौजूद अपने सहयोगियों के जरिए ड्रोन ड्रॉप के माध्यम से भारी मात्रा में हथियार, गोला-बारूद और आईईडी जैसी विस्फोटक सामग्री मंगवाई थी.

एजेंसियों को शक है कि इन हथियारों का इस्तेमाल पंजाब, दिल्ली और अन्य राज्यों में सिलसिलेवार धमाकों के लिए किया जाना था. जांच के दौरान एनआईए को यह भी पता चला कि आरोपियों की भर्ती सोशल मीडिया और एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग ऐप्स के जरिए की जा रही थी. युवाओं को कट्टरपंथ की ओर धकेलकर आतंकी गतिविधियों में शामिल किया जा रहा था. इसी कड़ी में एनआईए ने हरियाणा के सिरसा महिला थाना ग्रेनेड हमले मामले में भी नौ आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है. इनमें दो पाकिस्तानी हैंडलर और कई भारतीय सहयोगी शामिल हैं.

एजेंसी के मुताबिक, यह हमला भारत में दहशत फैलाने और पुलिस प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने की बड़ी साजिश का हिस्सा था. फिलहाल एनआइए फरार आरोपियों की तलाश में जुटी है और विभिन्न राज्यों में संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है. एजेंसियों का कहना है कि आने वाले दिनों में इस नेटवर्क से जुड़े और बड़े खुलासे हो सकते हैं.